भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4710

जिसका उत्तर, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक) को दिया गया

एलआईसी को आईडीबीआई की हिस्सेदारी बेचना

4710. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान आईडीबीआई की अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी एलआईसी को बेच दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आईडीबीआई की अपनी बाकी हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने एलआईसी के विनिवेश का निर्णय भी लिया है;

(घ) यदि हां, तो आईडीबीआई बैंक का भविष्य क्या होगा और आईडीबीआई में अपनी हिस्सेदारी को एलआईसी को बेचने और एलआईसी के विनिवेश के पीछे क्या तर्क है;

(ङ) सरकार को कुल कितनी हानि हुई है और अपने नुकसान की भरपाई के लिए बैंक को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(च) बैंकों के निजीकरण का काफी समय से विरोध कर रहे आईडीबीआई कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी, नहीं। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में 51% नियंत्रक हिस्सेदारी के अर्जन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार को इसके बारे में सूचना दी थी तथा सरकार ने शेयरधारिता कम करके बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को 50% से कम करने के संबंध में अपनी अनापत्ति की सूचना दी थी। तत्पश्चात्, एलआईसी ने बैंक में 51% की हिस्सेदारी अर्जित की। इसमें बैंक में सरकार द्वारा बेची गयी हिस्सेदारी शामिल नहीं है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता। यह भी उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह कहा था कि "पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। तथापि, इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक निजी पूँजी की आवश्यकता है, तदनुसार, आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की शेष शेयरधारिता शेयर बाजार के माध्यम से निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को बेचे जाने का प्रस्ताव है। शेयर बाजार में कंपनियों को सूचीबद्ध करने से कंपनियां अनुशासित होती हैं तथा उन्हें वित्तीय बाजारों तक पहुँच उपलब्ध होती है तथा इसके मूल्य का पता चलता है। यह इस प्रकार सृजित संपदा में भागीदारी के लिए खुदरा निवेशकों को अवसर भी प्रदान करता है। वर्तमान में सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से एलआईसी में अपनी शेयरधारिता बेचने का प्रस्ताव किया है।"

(ङ.): वैसी संस्थाएं, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी होती है, से सरकार को लाभांश प्राप्त होता है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक सरकार को बैंक द्वारा प्रदत्त लाभांश के रूप में 1,466.65 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

(च): बैंक ने सूचना दी है कि बैंक के कर्मचारियों का अभिशासन बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सेवा नियमों द्वारा जारी रहेगा।

*****